भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3087 का उत्तर

रेल पटरियों का नवीनीकरण

3087. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण रेल नेटवर्क, विशेषकर उत्तर-पूर्व रेलवे नेटवर्क में नवीनीकरण के लिए चिह्नित पटरी की लंबाई, किलोमीटर में (मार्ग किलोमीटर में) कितनी है;

(ख) गत सात वर्षों के दौरान रेल पटरी के नवीनीकरण और नई पटरी बिछाने के वर्ष-वार लक्ष्य क्या हैं;

(ग) विशेषकर झारखंड में लंबित कार्यों सहित ज़ोन-वार उक्त अवधि के दौरान कितने किलोमीटर वास्तविक मार्ग पर रेल पटरी का राज्य-वार नवीनीकरण और नई पटरी बिछाने का कार्य किया गया है;

(घ) पारसनाथ-मधुबन-गिरिडीह नई रेल लाइन परियोजना जिसकी आधारशिला वर्ष 2019 में रखी गई थी, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) बिहार और कोलकाता सहित राज्यों में रेल नेटवर्क के नवीनीकरण की स्थिति क्या है; और

(च) क्या सरकार का बिहार और कोलकाता सहित राज्यों में नई रेल लाइनें बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): रेलपथ का उन्नयन और नवीकरण करना निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। रेलपथ की आयु, ढोए गए यातायात, रेलपथ की स्थिति आदि के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार रेलपथ नवीकरण किया जाता है।

रेलपथ नवीकरण कार्य रेलपथ की स्थिति और अन्य विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए यथोचित प्राथमिकता निर्धारित करते हुए योजना बनाई जाती है और निष्पादित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलपथ अनुमेय गति पर रेलगाड़ियां चलान हेतु सुरक्षित हो।

2014-26 (फरवरी 20256 तक) के दौरान समूचे रेल नेटवर्क पर किए गए रेलपथ नवीकरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

नवीकृत रेलपथ	~ 54600 कि.मी.

उपर्युक्त रेलपथ नवीकरण में पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, बिहार और कोलकाता में स्थित रेलपथ शामिल हैं।

इसके अलावा, रेलपथ उन्नयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

i. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 कि.ग्रा. की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रेंथ की पटरियां, लोचदार बंधन वाले चौड़े और भारी प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर फैनशेप्ड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है।
ii. टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।
iii. ज्वाइंटों की वेल्डिंग से बचने के लिए 260 मीटर लंबे रेल पैनलों की आपूर्ति को बढ़ाना ताकि संरक्षा बेहतर हो।
iv. पहले उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक/बेहतर एसईजे के स्थान पर थिक वेब स्विच एक्सपैंशन ज्वाइंट्स का उपयोग किया जा रहा है।
v. पटरियों के लिए बेहतर वेल्डिंग तकनीक अर्थात फ्लैश बट वेल्डिंग को अपनाना।
vi. रेलपथ अनुरक्षण के लिए उच्च आउटपुट प्लेन टैम्पर और पॉइंटों एवं क्रॉसिंग टैम्पर्स का उपयोग करते हुए मशीनीकृत प्रणाली को अपनाना, ताकि रेलपथ की बेहतर अनुरक्षण और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

vii. परिसंपत्ति विश्वसनीयता में और सुधार लाने के लिए रेल ग्राइंडिंग मशीनों सहित अत्याधुनिक आधुनिक मशीनों की तैनाती।

viii. पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।

ix. रेल और वेल्ड के परीक्षण के लिए उन्नत फेज़्ड ऐरे तकनीक का उपयोग।

x. इष्टतम अनुरक्षण आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए व्यापक स्थिति मूल्यांकन हेतु एकीकृत रेलपथ निगरानी प्रणाली और दोलन निगरानी प्रणाली की तैनाती।

xi. यार्डों में रेलपथ मापदंडों की निरंतर रिकॉर्डिंग के लिए पोर्टेबल रेलपथ मापक ट्रॉली को अपनाना।

xii. सटीक अनुरक्षण इनपुट प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रेलपथ निरीक्षण रिकॉर्ड के एकीकरण और डेटा विश्लेषण के लिए वेब सक्षम रेलपथ प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करना।

पारसनाथ-गिरीडीह-मधुबन नई लाइन:

पारसनाथ-गिरीडीह-मधुबन नई लाइन परियोजना को वर्ष 2018-19 में 903 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर झारखंड सरकार के साथ 50:50 लागत भागीदारी के आधार पर शुरू किया गया था। तदनुसार, रेलवे ने राज्य सरकार से अपने हिस्से की लागत जमा कराने का अनुरोध किया था। बहरहाल, झारखंड सरकार ने अपना हिस्सा अभी तक जमा नहीं कराया है। परिणामस्वरूप परियोजना में प्रगति नहीं हुई है।

झारखंड

हाल के वर्षों में बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली अवसरंचना परियोजनाओं के लिए परिव्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹457 करोड़/वर्ष
2025-26	₹7306 करोड़ (लगभग 16 गुना)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 2363 किलोमीटर कुल लंबाई वाली 26 परियोजनाएं (9 नई लाइन और 17 दोहरीकरण), जिनकी लागत 47,729 करोड़ रुपए है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 598 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाएं कमीशन कर दी गई है तथा मार्च, 2025 तक 15,845 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2025 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	9	749	156	4239
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	17	1614	442	11606
कुल	26	2363	598	15845

झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाले नए रेलपथ को कमीशन करने/बिछाने का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नये रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	287 कि.मी.	57.4 कि.मी.
2014-25	1316 कि.मी.	119.64 कि.मी. (2 गुना से अधिक)

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2022-2023, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष अर्थात 2025-26) के दौरान, झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाले कुल 85 सर्वेक्षण (18 नई लाइन, 67 दोहरीकरण) जिनकी कुल लंबाई 3303 किलोमीटर है, स्वीकृत किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹4,380 करोड़ प्रति वर्ष
2025-26	₹13,955 करोड़ (3 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 67,991 करोड़ रुपए की लागत से कुल 4,402 किलोमीटर लंबाई की 42 परियोजनाएं (12 नई लाइनें, 04 आमान परिवर्तन और 26 दोहरीकरण) स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,702 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2025 तक 23,410 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया जा चुका है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	12	1,032	337	11,368
आमान परिवर्तन	04	1,201	854	3,673
दोहरीकरण/बहुपथन	26	2,169	511	8,370
कुल	42	4,402	1,702	23,410

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	रामपुरहाट-मंदारहिल नई लाइन और रामपुरहाट-मुरारई तीसरी लाइन (159 किलोमीटर)	1500
2	अजीमगंज-मुर्शिदाबाद नई लाइन (7 किलोमीटर)	164
3	बर्धमान-कटवा आमान परिवर्तन (52 किलोमीटर)	696
4	अहमदपुर-कटवा आमान परिवर्तन (52 किलोमीटर)	440
5	पाँशकुड़ा-खड़गपुर दोहरीकरण (45 किलोमीटर)	408
6	लालगोला-जियागंज दोहरीकरण (23 किलोमीटर)	124
7	कृष्णनगर-बेथुयाडहरी दोहरीकरण (28 किलोमीटर)	152
8	नबद्वीपधाम-पाटुली दोहरीकरण (22 किलोमीटर)	170
9	बेथुयाडहरी-प्लासी दोहरीकरण (23 किलोमीटर)	132
10	अम्बिका कालना-नबद्वीपधाम दोहरीकरण (23 किलोमीटर)	145
11	नलहाटी-सागरदिघि दोहरीकरण (26 किलोमीटर)	193
12	तमलुक जंक्शन- बासुलिया सुताहाटा दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	245
13	प्लासी-जियागंज दोहरीकरण (54 किलोमीटर)	234
14	अजीमगंज-मणिग्राम दोहरीकरण (21 किलोमीटर)	150
15	न्यू कूचबिहार-गुमानीहाट दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	330

16	न्यू कूचबिहार-सामुकतला रोड दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	445
17	सैंथिया-तारापीठ तीसरी लाइन (22 किलोमीटर)	186
18	आमबाड़ी फालाकाटा - न्यू मैनागुड़ी दोहरीकरण (37 किलोमीटर)	843
19	बैंडेल-बोइंची-तीसरी लाइन (31 किलोमीटर)	546
20	बोइंची-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन (26 किलोमीटर)	424
21	बाज़ार सौ-अजीमगंज जंक्शन दोहरीकरण (42 किलोमीटर)	343
22	सागरदिघी-मालदा टाउन दोहरीकरण (25 किलोमीटर)	248
23	खड़गपुर-नारायणगढ़ तीसरी लाइन (24 किलोमीटर)	270
24	मनिग्राम-निमतिता दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	713
25	पुरुलिया-कोटशिला दोहरीकरण (36 किलोमीटर)	393

पश्चिम बंगाल में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जिन्हें शुरू किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	तारकेश्वर-बिष्णुपुर नई लाइन (83 किलोमीटर)	1542
2	सिवोक-रंगपो नई लाइन (44 किलोमीटर)	11973
3	बालुरघाट-हिली नई लाइन (30 किलोमीटर)	1209
4	कालियागंज-बुनियादपुर नई लाइन (33 किलोमीटर)	1147
5	कटिहार-कुमेदपुर और कटिहार-मुकुरिया दोहरीकरण (65 किलोमीटर)	943

6	खड़गपुर-आदित्यपुर तीसरी लाइन (132 किलोमीटर)	3250
7	नारायणगढ़-भद्रक तीसरी लाइन (153 किलोमीटर)	2136
8	चांडिल-अनारा-दामोदर तीसरी लाइन (121 किलोमीटर)	1932
9	कालीपहाड़ी-बख्तरनगर 5वीं लाइन (18 किलोमीटर)	350
10	डानकुनि-बाल्टीकुरी तीसरी और चौथी लाइन (18 किलोमीटर)	429
11	मुरारई-बड़हरवा तीसरी लाइन (49 किलोमीटर)	935
12	राणाघाट-कृष्णानगर सिटी तीसरी लाइन (26 किलोमीटर)	446
13	अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन (57 किलोमीटर)	1630

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2022-2023, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष अर्थात 2025-26) के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाले कुल 97 सर्वेक्षण (10 नई लाइन, 87 दोहरीकरण) जिनकी कुल लंबाई 4004 किलोमीटर है, स्वीकृत किए गए हैं।

कोलकाता मेट्रो :

कोलकाता में मेट्रो परियोजना 1972 में शुरू की गई। तब से कमीशन की गई मेट्रो का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन की गई मेट्रो
1972 से 2014 (42 वर्ष)	28 कि.मी.
2014 से 2025 (11 वर्ष)	45 कि.मी.

वर्तमान में, कोलकाता और उसके आसपास कुल 52 कि.मी. के 4 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से 20 कि.मी. भूमि अधिग्रहण और उपयोगिताओं संबंधी समस्याओं के कारण रुके हुए हैं, जो राज्य सरकार से संबंधित हैं। इन कॉरिडोर की वस्तुस्थिति नीचे दी गई है:

i. जोका - एस्प्लानेड (14 कि.मी.):- जोका - माझेरहाट (7.74 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है और माझेरहाट से एस्प्लेनेड (6.62 कि.मी.) तक का शेष कार्य शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, कार्य की प्रगति निम्नलिखित समस्याओं के कारण प्रभावित है:

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	खिदिरपुर मेट्रो स्टेशन	1. कोलकाता सशस्त्र पुलिस की स्थायी संरचना वाली 837 वर्ग मीटर की स्थायी और अस्थायी संरचना वाली 1702 वर्ग मीटर भूमि को उपयोगिताओं की शिफ्टिंग और सड़क यातायात के डायवर्जन के लिए अपेक्षित थी, जिसके लिए 24.08.2020 को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। 2. पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें हुईं। 3. राज्य सरकार ने लगभग 5 वर्ष के बाद अंतत: 09.07.2025 को अनुमोदन प्रदान किया।
2.	डॉ. बी.सी. राय मार्केट	1. एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए, रक्षा भूमि पर बी.सी. रॉय मार्केट में 528 अवैध दुकानों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना अपेक्षित था। मार्केट के अस्थायी स्थानांतरण के लिए अनापित्त प्रमाण-पत्र का प्रस्ताव फरवरी, 2022 में प्रस्तुत किया गया था। 2. अस्थायी स्थानांतरण के लिए भी दुकानों का निर्माण किया गया। 3. राज्य सरकार से स्थानांतरण हेतु सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। लोक निर्माण विभाग के साथ नियमित समन्वय भी किया जा रहा है। साथ ही, 30.07.2025 को कोलकाता के माननीय महापौर के साथ बैठक की गई। 4. यह मामला 3.5 से अधिक वर्षों से लंबित है।

ii. न्यू गरिया - दमदम एयरपोर्ट (32 कि.मी.): न्यू गरिया - बेलाघाटा (9.8 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है और बेलाघाटा से दमदम एयरपोर्ट (22.2 कि.मी.) तक के शेष कार्य को शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, कार्य की प्रगति निम्नलिखित समस्याओं के कारण प्रभावित है:

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	चिंगरीघाटा क्रॉसिंग (बेलाघाटा - गौर किशोर घोष स्टेशन के बीच)	1. चिंगरीघाटा क्रॉसिंग पर प्रत्येक साइड पर 3+3 रातों (प्रत्येक 8 घंटे) के लिए वायडक्ट सेगमेंट की लॉन्चिंग के कारण अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन अपेक्षित है। यह प्रस्ताव फरवरी, 2025 में पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत किया गया था। 2. कोलकाता यातयात पुलिस की वांछानुसार परिवर्तित मार्ग पहले ही फरवरी, 2025 में निर्मित किया जा चुका है। 3. अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गई। 4. दस माह बीत जाने के बाद भी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

iii. नोआपारा - बारासात (18 कि.मी.): नोआपारा-जय हिन्द एयरपोर्ट (6.77 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है और जय हिन्द एयरपोर्ट से माइकल नगर तक का कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, न्यू बैरकपुर से बरासात (7.5 कि.मी.) तक का कार्य भूमि अधिग्रहण और राज्य अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण संबंधी मुद्दों के कारण रोक दिया गया है।

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	न्यू बैरकपुर से बारासात	1. इस खंड में भूमि अधिग्रहण (23000 वर्ग मीटर) और अत्यधिक अतिक्रमणों (1277 झोपड़ियाँ, 764 दुकानें) को हटाना शामिल है। 2. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी मामले का समाधान नहीं किया गया है।

iv. **बराहनगर - बैरकपुर - दक्षिणेश्वर (14.5 कि.मी.): बराहनगर - दक्षिणेश्वर (2 कि.मी.) का कार्य कमीशन कर दिया गया है और बराहनगर से बैरकपुर (12.5 कि.मी.) तक का शेष कार्य राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा मार्ग में उपयोगिताओं को स्थानांतरित करने में विलंब के कारण रुका हुआ है।**

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	बराहनगर से बैरकपुर	1. बी.टी. रोड के समानांतर मूल संरेखण पर वर्ष 2011 में मेट्रो रेलवे, आरवीएनएल और कोलकाता नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार सहमति बनाई गई थी। 2. समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान पाइपलाइन को 64 इंच की नई पाइपलाइन से प्रतिस्थापित किया जाना था। 3. 64 इंच पाइपलाइन की शिफ्टिंग का कार्य वर्ष 2012 में पूरा हो गया था। 4. अब, राज्य सरकार 90 इंच की नई पाइपलाइन के निर्माण पर जोर देर रही है जिसकी लागत लगभग 1400 करोड़ रुपए है। 5. इस मांग को परियोजना की लागत और समझौता ज्ञापन के प्रावधान के तहत शामिल नहीं किया गया है। 6. पश्चिम बंगाल सरकार से अभी तक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार:

बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए परिव्यय का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,132 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	10,066 करोड़ रु. (लगभग 9 गुना)

2009-14 और 2014-25 को दौरान बिहार राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए गए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	318 कि.मी.	63.6 कि.मी.
2014-25	1899 कि.मी.	172.6 कि.मी. (2.5 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 86107 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 4,663 किलोमीटर लंबाई की 52 परियोजनाएं (31 नई लाइनें, 01 आमान परिवर्तन और 20 दोहरीकरण) स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,250 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2025 तक 29,353 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया जा चुका है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	नई लाईन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण की कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	31	2,691	516	16,814
आमान परिवर्तन	1	69	52	544
दोहरीकरण/बहुपथन	20	1,904	446	11,995
कुल	52	4,663	1,014	29,353

हाल ही में बिहार राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली संपन्न की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1	मुंगेर पुल (19 कि.मी.)	2774
2	कोसी पुल (22 कि.मी.)	516
3	पटना पुल (40 कि.मी.)	3555
4	हाजीपुर-बछवारा दोहरीकरण (72 कि.मी.)	930
5	किउल-गया दोहरीकरण (123 कि.मी.)	1200
6	कारोटा पटनेर-मनकठा - सतह त्रिभुज (8 कि.मी.)	129
7	रामपुरहाट-मंदारहिल नई लाइन और रामपुरहाट-मुरराय-तीसरी लाइन (160 कि.मी.)	1500
8	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज और नरकटियागंज-भिखना टोरी आमान परिवर्तन (295 कि.मी.)	1193
9	सकरी-लौकाहा बाजार-निर्माली और सहारसा-फोर्ब्सगंज आमान परिवर्तन (206 कि.मी.)	2113
10	बख्तियारपुर फ्लाईओवर (4 कि.मी.)	402
11	कोसी नदी पर पुल सहित कटारेह-कुर्सेला पट्टी का दोहरीकरण (7 कि.मी.)	222
12	अररिया-गल्गलिया नई लाइन (111 कि.मी.)	4415

बिहार में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जिन्हें शुरू किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	सीतामढ़ी-शेओहर नई लाइन (28 कि.मी.)	567
2	सकरी -हसनपुर नई लाइन (76 कि.मी.)	735
3	खगड़िया-कुशेश्वरस्थान नई लाइन (42 किमी)	1,511
4	नेओरा-दानियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा नई लाइन (166 कि.मी.)	2,200
5	कोडरमा-तिलैया नई लाइन (65 कि.मी.)	1,626
6	हाजीपुर-सगौली नई लाइन (151 कि.मी.)	2,087
7	अररिया-सुपौल नई लाइन (96 कि.मी.)	1,605
8	विक्रमशिला-कटरिया नई लाइन गंगा नदी पर पुल सहित (26 कि.मी.)	2,090
9	पिरपैंती-जसीडीह नई लाइन (97 किमी) हंसडीहा-गोडड़ा नई लाइन (30 किमी) को छोड़कर	2,140
10	सोननगर-पतरातू मल्टीट्रैकिंग (291 कि.मी.)	5,148
11	समस्तीपुर - दरभंगा दोहरीकरण (38 किलोमीटर)	624
12	रामपुर दुमरा-ताल-राजेंद्र पुल-अतिरिक्त पुल और दोहरीकरण (14 कि.मी.)	1,677
13	सगौली-वाल्मिकीनगर दोहरीकरण (110 कि.मी.)	1,280
14	मुजफ्फरपुर-सगौली दोहरीकरण (101 कि.मी.)	1,465
15	बरौनी-बछवाड़ा तीसरी एवं चौथी लाइन (32 कि.मी.)	124
16	सोननगर-अंडाल मल्टीट्रैकिंग (749 कि.मी.)	12,334
17	बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया दोहरीकरण (104 कि.मी.)	2,192
18	बख्तियारपुर-फतुआ तीसरी एवं चौथी लाइन (24 कि.मी.)	931

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2022-2023, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष अर्थात 2025-26) के दौरान, बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाले कुल 92 अदद सर्वेक्षण (16 नई लाइन, 76 दोहरीकरण) जिनकी कुल लंबाई 4530 किलोमीटर है, स्वीकृत किए गए हैं।

रेल परियोजनाओं का जोनल रेलवे वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मापदंडों/कारकों पर निर्भर करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनुमानित यातायात अनुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रथम और अंतिम छोर संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और वैकल्पिक मार्गों प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन
- राज्य सरकारों केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएं
- सामाजिक आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण,
- वन संबंधी मंजूरी,
- अतिलंघनकारी साधनों का स्थानांतरण,
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां,
- क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां,

- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति,**
- **परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या,**

ये सभी कारक परियोजना(ओं) के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

****